

वित्तीय शिक्षा के लिए राष्ट्रीय रणनीति 2020-25*

शक्तिकान्त दास

वित्तीय शिक्षा के लिए राष्ट्रीय रणनीति पर इस वेबिनार में आधार व्याख्यान देने हेतु आमंत्रण के लिए एनसीईआर को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। वेबिनार के लिए यह विषय चुनने की एनसीईआर की विचारशील पहल की मैं सराहना करता हूँ। ऐसे समय में जब हम जीवन और आजीविका की एक अभूतपूर्व क्षति वाले वर्ष की समाप्ति की ओर बढ़ रहे हैं, तो उचित होगा कि वित्तीय समावेशन और साक्षरता पर विचार किया जाए जिसके वित्तीय स्थिरता के लिए व्यापक समष्टि स्तर के निहितार्थों के साथ-साथ व्यक्ति के वित्तीय कल्याण की दृष्टि से व्यक्ति संकेतार्थ भी हैं।

भूमिका

कामकाजी आयु में आबादी के एक बड़े हिस्से वाला भारत दुनिया में पहले से ही क्रय शक्ति समानता के मामले में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है जो यूएसडी 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य रखता है। सरकार व्यापक संरचनात्मक सुधारों के माध्यम से श्रृंखलाबद्ध रूप से स्तर पर नपे-तुले कदम उठाते आ रही है। हमें एक बड़ी युवा आबादी की आकांक्षाओं को पूरा करके जनसांख्यिकीय लाभांश का दोहन करने की आवश्यकता है। इसके लिए जरूरी है शिक्षा, प्रशिक्षण और अवसर के रूप में एक सक्षम वातावरण और बुनियादी ढांचा बनाने की। मानव संसाधन की गुणवत्ता, अर्थव्यवस्था का और अधिक औपचारिकीकरण, उच्च ऋण जीडीपी अनुपात और अधिक वित्तीय समावेश जनसांख्यिकीय लाभांश और त्वरित विकास को प्राप्त करने के लिए आवश्यक कारक हैं, जो हमारी अर्थव्यवस्था को वांछित स्तर तक पहुंचाने में मदद करेंगे।

* * 16 दिसंबर, 2020 को राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान परिषद (एनसीईआर) द्वारा 'भारत में निवेशक शिक्षा में निवेश : कार्यवाई हेतु प्राथमिकताएं' पर आयोजित वेबिनार में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर श्री शक्तिकान्त दास का आधार व्याख्यान।

ऋण जीडीपी अनुपात में सुधार के लिए, ऋण की उपलब्धता और ऋण की लागत को संपार्श्विक सुरक्षा पर कम निर्भरता और अधिक नकदी-प्रवाह-आधारित उधार पर ध्यान देने की आवश्यकता है। क्रेडिट ब्यूरो और प्रस्तावित पब्लिक क्रेडिट रजिस्ट्री (पीसीआर) ढाँचे से क्रेडिट प्रवाह के साथ-साथ क्रेडिट संस्कृति में सुधार की उम्मीद है। वित्तीय समावेश के संबंध में सरकार और रिजर्व बैंक द्वारा कई कदम उठाए गए हैं। परिणामस्वरूप आबादी के बड़े और अब तक शामिल नहीं हुए वर्गों को औपचारिक वित्तीय दायरे में लाया गया है। इस संदर्भ में, वित्तीय शिक्षा को बढ़ावा देना और गहरा करना हमारी सामूहिक क्षमता को साकार करने के हमारे प्रयास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

वित्तीय समावेश पहल-अब तक

भारत में वित्तीय समावेश के प्रयास पहल 1954 में अखिल भारतीय ग्रामीण ऋण सर्वेक्षण के बाद सहकारी समितियों को बढ़ावा देने के साथ शुरू हुए, जिसे आगे चलकर प्रमुख निजी क्षेत्र के बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बाद शाखा नेटवर्क के विस्तार, लीड बैंक योजना का शुभारंभ, स्वयं सहायता समूह का प्रचार (एसएचजी) संयुक्त देयता समूह (जेएलजी) बैंकिंग कॉर्रेस्पॉन्डेंट (बीसी) मॉडल का कार्यान्वयन, बैंकिंग आउटलेट के विस्तार, भुगतान बैंकों के निर्माण, छोटे वित्त बैंकों द्वारा आगे बढ़ाया गया। हाल के वर्षों में सबसे बड़ा प्रभाव जनधन खातों के खुलने और प्रधानमंत्री मुद्रा योजना पीएमएमवाई के कार्यान्वयन से पड़ा।

2014 में प्रधानमंत्री जनधन योजना (पीएमजेडीवाई) की शुरुआत से औपचारिक बैंकिंग सेवा' प्रायः हर घर तक पहुंच गई जिसके साथ सस्ते ऋण, बीमा और पेंशन योजनाओं के लाभ भी उपलब्ध थे। इसको बीसी मॉडल जैसे अभिनव बैंकिंग चैनलों के माध्यम से अच्छा सहयोग मिला जिसके द्वारा बैंकिंग सेवाओं को अंतिम छोर तक पहुंचाने का प्रयास हुआ। प्रौद्योगिकी की वजह से डिजिटल वित्तीय सेवाओं में बड़ी उन्नति हुई है। जनधन

¹ 2 दिसंबर, 2020 की स्थिति के अनुसार 41.38 करोड़ लाभार्थी बैंक से जुड़े, लाभार्थियों के खातों में, ₹130,932.33 करोड़ शेष - <https://www.pmjdy.gov.in>

खाता, आधार और मोबाइल (जेएएम) के परितंत्र (इकोसिस्टम) ने वित्तीय समावेश की दुनिया में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं।

इसके अलावा जमीनी स्तर पर डिजिटल बुनियादी ढांचे को सक्षम बनाने और एक सुविधाजनक सुरक्षित और सस्ते तरीके से डिजिटल भुगतानों को सार्वभौमिक बनाने की दिशा में प्रगति में तेजी लाने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। इनमें महत्वपूर्ण है, रिजर्व बैंक द्वारा अक्टूबर 2019 में शुरू किया गया पायलट प्रोजेक्ट जिसके अंतर्गत प्रत्येक राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में एक जिले को 100% डिजिटल रूप से सक्षम बनाना है। आठ आकांक्षात्मक जिलों के साथ 42 जिले इस पहल का हिस्सा हैं। आवश्यक डिजिटल परितंत्र के अलावा, हित धारकों द्वारा लक्षित समूहों को वित्तीय शिक्षा प्रदान करने पर केंद्रित ध्यान पायलट परियोजना के उद्देश्यों को पूरा करने की दिशा में एक बड़ा योगदान देगा और अन्य जिलों में ऐसे प्रयासों को आगे ले जाने का एक खाका प्रदान करेगा।

वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद (एफ एस डी सी) ने वित्तीय समावेश के लिए राष्ट्रीय रणनीति (एन एस एफ आई) दस्तावेज़ को मंजूरी दे दी, जिसे इस वर्ष आरबीआई ने 10 जनवरी 2020 को लॉन्च किया था। समावेशी विकास को आगे बढ़ाने के लिए एनएसएफआई में बहु हित धारक (मल्टी स्टेक होल्डर) दृष्टिकोण से सभी नागरिकों को सुरक्षित और पारदर्शी तरीके से वित्तीय सेवाओं को उपलब्ध, सुलभ और सस्ती बनाने की परिकल्पना है।

भारत में वित्तीय शिक्षा

सरकार और वित्तीय क्षेत्र के नियामकों के लिए एक महत्वपूर्ण नीति एजेंडा

वित्तीय समावेश में वृद्धि के साथ ग्राहक संरक्षण और वित्तीय शिक्षा को बढ़ाने की आवश्यकता है। ताकि लोग बिना किसी हिचकिचाहट के औपचारिक वित्तीय सेवाओं का उपयोग करते रहें। यह बताने की आवश्यकता नहीं कि अधिक जागरूकता और विनियमित इकाइयों द्वारा उपयुक्त वित्तीय उत्पादों और

सेवाओं तक पहुँच का रास्ता बनाकर बनाकर वित्तीय शिक्षा मांग पक्ष का प्रतिसाद तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वित्तीय शिक्षा के माध्यम से व्यक्तियों और उनके परिवारों की वित्तीय समुत्थानशीलता को भी मजबूत किया जा सकता है। इन विविध उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। ऐसे दो प्रयासों की मैं चर्चा करता हूँ-

वित्तीय शिक्षा के लिए राष्ट्रीय केंद्र (एन सी एफ ई) की स्थापना

वित्तीय शिक्षा के लिए राष्ट्रीय रणनीति (एनएसएफआई) के अनुसार जनसंख्या के सभी वर्गों को भारत भर में वित्तीय शिक्षा देने और बढ़ावा देने के लिए एनसीएफई को चार वित्तीय क्षेत्र नियामकों द्वारा धारा 8 (लाभ के लिए नहीं) कंपनी के रूप में स्थापित किया गया है। एनसीएफई सेमिनारों, कार्यशालाओं, सम्मेलनों, प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से वित्तीय शिक्षा अभियान चलाती है ताकि लोग धन का प्रबंधन सही ढंग से कर सकें और इस प्रकार उनकी वित्तीय स्थिति अच्छी हो।

वित्तीय साक्षरता केंद्र (सीएफएल) परियोजना- सामुदायिक पद्धति से वित्तीय शिक्षा देने का एक अभिनव तरीका

वित्तीय साक्षरता के लिए ब्लॉक स्तर पर चुनिंदा बैंकों और गैर सरकारी संगठनों (एनजीओ) को शामिल करते हुए रिजर्व बैंक ने 2017 में सीएफएल परियोजना की अवधारणा एक अभिनव व सहभागी पद्धति के रूप में प्रस्तुत की। 100 ब्लॉकों में पायलट आधार पर शुरू की गई यह परियोजना अब चरणबद्ध तरीके से मार्च 2024 तक पूरे देश में लागू होने जा रही है। यह 4 दिसंबर 2020 को मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) के वक्तव्य के अंतर्गत की गई घोषणाओं में से एक थी। आगे चलकर आपूर्ति पक्ष पर संस्थागत प्रयासों में वृद्धि के साथ तालमेल बिठाने के लिए मांग पक्ष पर समुदाय की अधिक भागीदारी और ग्रहणशीलता सुनिश्चित करते हुए परियोजना में वित्तीय समावेशन के साथ-साथ शिक्षण के प्रतिमान को बदलने की परिकल्पना की गई है।

³ एनएसएफई 20 अगस्त 2020 को लॉन्च किया गया। <https://rbidocs.rbi.org.in/rdocs/PublicationReport/Pdfs/NSFIREPORT100119FF91DAA6B73B497A923CC11E0811776D.PDF>

² <https://rbidocs.rbi.org.in/rdocs/content/pdfs/NSFIREPORT100119.pdf>

कोविड-19 महामारी के दौरान वित्तीय शिक्षा के प्रसार से मिली सीख

कोविड-19 संबंधी राष्ट्रव्यापी तालाबंदी (लॉकडाउन) और विभिन्न सार्वजनिक स्थानों पर लोगों के बड़े पैमाने पर एकत्र होने पर प्रतिबंधों के परिणाम स्वरूप पारंपरिक वित्तीय साक्षरता शिविरों के आयोजन में व्यवधान आया है। इस अवधि के दौरान देशभर में सोशल मीडिया, मास मीडिया (स्थानीय टीवी चैनलों रेडियो सहित) के प्रयोग, स्थानीय स्कूल शिक्षा बोर्ड से संपर्क, स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) के प्रशिक्षण मिशनों आदि विभिन्न तरीकों से वित्तीय शिक्षा का प्रसार जारी रखा गया।

वित्तीय शिक्षा के लिए राष्ट्रीय रणनीति (एनएसएफई 2020-2025)

दृष्टि (विज्ञान), रणनीतिक उद्देश्य और 5सी पद्धति

वित्तीय शिक्षा रणनीतिक स्तंभों में से एक है, जो वित्तीय शिक्षा के लिए राष्ट्रीय रणनीति (2020-2025) के लिए व्यापक संदर्भ निर्धारित करता है। एनएसएफई (2020- 2025) ने वित्तीय रूप से जागरूक और सशक्त भारत बनाने की महत्वकांक्षी विज्ञान तय किया है। यह वित्तीय संस्थानों (बैंक व गैर बैंक दोनों), शिक्षा संस्थानों, हित धारकों और औद्योगिक इकाइयों की भूमिका को बढ़ाकर बैंकिंग, बीमा, पेंशन और निवेश के सभी क्षेत्रों में वित्तीय शिक्षा के विभिन्न पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करता है। स्कूली बच्चों, शिक्षक, युवा, महिलाओं, नए कर्मचारी, एमएसएमई के नए उद्यमियों, वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांग जनों और अशिक्षितों जैसे विभिन्न लक्ष्य समूहों तक पहुँच के लिए लक्षित मॉड्यूलों सहित नवोन्मेषी तकनीकों और वितरण के डिजिटल तरीकों की परिकल्पना की गई है। इसके अलावा डिजिटल वित्तीय सेवाओं के सुरक्षित उपयोग और शिकायत निवारण उपायों के बारे में जागरूकता बढ़ाने पर भी जोर दिया गया है। साक्ष्य आधारित नीति निर्माण के महत्व को ध्यान में रखते हुए, वित्तीय शिक्षा में प्रगति के मूल्यांकन के तरीकों को भी रणनीतिक उद्देश्यों में रखा गया है।

रणनीति में वित्तीय शिक्षा के प्रसार के लिए प्रासंगिक **सामग्री/कंटेंट** (स्कूलों और कॉलेजों और प्रशिक्षण प्रतिष्ठानों के पाठ्यक्रम सहित) के विकास; वित्तीय सेवाओं और शिक्षा प्रदान करने वाले मध्यस्थों की **क्षमता (कैपेसिटी)**; उपयुक्त संप्रेषण रणनीति के माध्यम से वित्तीय साक्षरता के **समुदाय (कम्यूनिटी)** चालित मॉडल के सकारात्मक प्रभाव के अधिकाधिक उपयोग; और विभिन्न हित धारकों के बीच **सहयोग (कॉलेबोरेशन)** में वृद्धि की '5सी' पद्धति ('5सी' एप्रोच) शामिल है।

आगे का रास्ता और निष्कर्ष

डिजिटल ज्ञान से लैस नई पीढ़ी के कर्मक्षेत्र में आने, शहरी-ग्रामीण विभाजन को मिटाने वाले सोशल मीडिया और नीतिगत हस्तक्षेप को आकार देने वाली प्रौद्योगिकी से देश में वित्तीय समावेश में बड़ी तेजी आनी तय है। आगे, देश भर में बैंक खातों की सार्वभौमिक पहुँच का दोहन करते हुए, अधिक ग्राहक सुरक्षा के साथ मांग से जुड़ी बाधाओं को दूर करके टिकाऊ ऋण, निवेश बीमा और पेंशन उत्पादों के और गहरे पैठ पर अधिक ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है।

वित्तीय शिक्षा में हस्तक्षेप को विभिन्न लक्षित दर्शकों/श्रोताओं को ध्यान में रखते हुए ढालना (स्थानीय भाषा और स्थानीय सेटिंग) होगा। वित्तीय साक्षरता की हमारी यात्रा में ब्लॉक स्तर पर देश भर में सीएफएल प्रोजेक्ट का विस्तार समुदाय चालित सहभागी दृष्टिकोण की आधारशिला होगी।

तकनीक सक्षम बनाने का एक महान साधन है, पर इससे समाज के कुछ वर्ग छूट भी सकते हैं। जो अब तक बाहर छूटे हैं, आबादी के उन तबकों के बीच, औपचारिक वित्तीय सेवाओं में विश्वास पैदा कराना जरूरी है। उचित वित्तीय शिक्षा और जागरूकता के माध्यम से साइबर सुरक्षा, डेटा गोपनीयता, अपविक्रय (मिस सेलिंग), ग्राहक संरक्षण और शिकायत निवारण के मुद्दों पर कार्रवाई के लिए जैसे पर्याप्त सुरक्षा उपायों को सुदृढ़ करने की आवश्यकता है। ये बातें वित्तीय शिक्षा प्रदाताओं पर बड़ी जिम्मेदारी डालते हैं।

अंत में, मैं कहना चाहूंगा कि हमारे जैसे बड़े देश में जहाँ लोगों में आकांक्षाएं हैं, वित्तीय शिक्षा केवल वित्तीय क्षेत्र के नियामकों की जिम्मेदारी नहीं बन सकती। इस पहलू को एनएसएफई दस्तावेज में रेखांकित किया गया है, जिसमें सभी की वित्तीय भलाई के लिए एक बहु हितधारक दृष्टिकोण को आगे रखने की सिफारिश की गई है। आगे, अधिकाधिक शिक्षा संस्थानों, उद्योग निकायों, तथा थिंक टैंकों, अनुसंधान

संस्थाओं जैसे हितधारकों को उचित जागरूकता अभियानों के माध्यम से वित्तीय साक्षरता बढ़ाने की जिम्मेदारी उठाने के लिए सामने आना चाहिए। मैं ऐसे प्रत्येक व्यक्ति और संस्था को आमंत्रित करता हूँ, कि वे आर्थिक रूप से जागरूक और सशक्त भारत के निर्माण के माध्यम से हमारे राष्ट्र के निर्माण के मिशन से जुड़ें।

धन्यवाद।